भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2664
जिसका उत्तर बुधवार, 10 अगस्त, 2016 को दिया जाना है

**बिजली से चलने वाले वाहनों हेतु लिथियम बैटरियों के विनिर्माण हेतु निधि**

**2664. श्रीमती रेणुका चौधरी:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिजली से चलने वाले वाहनों हेतु लिथियम बैटरियों के विनिर्माण के लिए निधि स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा शत प्रतिशत विद्युत और हाइब्रिड वाहनों की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**
**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री**
**(श्री बाबुल सुप्रियो)**

**(क):** जी, नहीं।

**(ख):** उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**(ग):** भारत सरकार ने 2011 में नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का अनुमोदन किया और तत्पश्चात् 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 का शुभारंभ किया गया था। इस मिशन के भाग के रूप में, 1 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित करने के लिए भारी उद्योग विभाग द्वारा फेम-इंडिया स्कीम (भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण) अधिसूचित की गई है। इस स्कीम को 2020 तक छह वर्षों की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है और नियत अवधि के अंत तक आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु इस दौरान हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहन बाजार विकास तथा इसके विनिर्माण के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य सभी वाहन सेगमेंटों अर्थात दुपहिया, तिपहिया ऑटो, यात्री चौपहिया वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन देना है। इस स्कीम का उद्देश्य लगभग 9500 मिलियन लीटर के बराबर ईंधन की संचयी बचत करना है जिससे वर्ष 2020 तक 6-7 मिलियन वाहन प्रतिवर्ष बाजार में उतारने के लक्ष्य के साथ प्रदूषण तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2 मिलियन टन कमी लाई जा सके।

*******